निवेशक को 13 साल बाद न्याय ब्याज समेत पैसे लौटाएगा बिल्डर

र नोएडा। दिल्ली के एक क्ति को बिल्डर के खिलाफ 3 साल बाद जिला उपभोक्ता रम से न्याय मिला है। बुधवार फोरम ने नीति श्री फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को याज समेत जमा धनराशि वापस रने का आदेश दिया है। बिल्डर 30 दिन के अंदर साधारण र्षिक ब्याज के साथ जमा नराशि आवंटी को देनी होगी। दी ने बताया कि बेटी की शादी लिए बिल्डर के प्रोजेक्ट में वेश किया था।

दिल्ली निवासी नीरज जैन का इक सर्विस स्टेशन है। उन्होंने ताया कि 2005 में नीति श्री ल्डर ने एनएच-58 पर र्षपुरम नाम से प्रोजेक्ट लांच किया था। उसमें 175 वर्ग मीटर भूखंड बुक कराया था। बुकिंग समय 2.85 लाख दिए थे। ल्डर ने दो साल में कब्जा देने वादा किया। 2007 में बिल्डर यहां से फोन आया, कहा कि रकार बदलने से प्रोजेक्ट समय र शुरू नहीं हो पा रहा है। बिल्डर 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कीमत बढ़ाकर पैसा वापस लेने या दूसरी जगह भूखंड लेने का ऑफर दिया। नीरज भूखंड लेने को तैयार हो गए, लेकिन बाद में बिल्डर ने भूखंड नहीं दिया। 2008 में नीरज ने उपभोक्ता फोरम में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। लंबी सुनवाई के बाद 2014 में फोरम ने फैसला सुनाया और बिल्डर को भूखंड देने या फिर बिना ब्याज के पैसे वापस करने का आदेश दिया, लेकिन बिल्डर ने भूखंड देने से इंकार कर दिया। नीरज ने ब्याज समेत पैसे वापस मांगे। चार साल सुनवाई के बाद बुधवार को फोरम ने नीरज के पक्ष में फैसला सुनाया। ब्यूरो

टोकन से मुक्ति, क्यूआर कोड से खुलेगा मेट्रो स्टेशन का प्रवेश द्वार

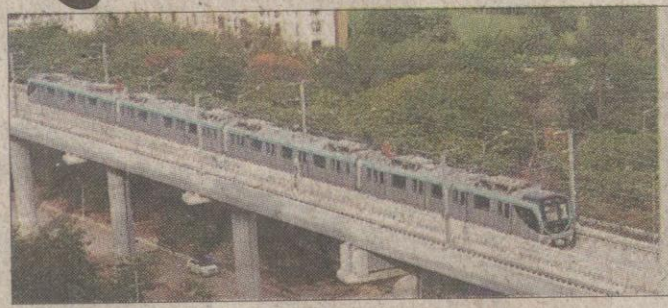

नोएडा-ग्रेनो मेट्रो कॉरिडोर के स्टेशनों के प्रवेश और निकासी द्वार पर होगा प्रयोग

रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स आर्गेनाईजेशन की टीम सोमवार को ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर पर पहुंच गई। इसके साथ ही मेट्रो का औपचारिक ट्रायल शुरू हो गया।

अमर उजाला ब्यूरो

नोएडा।

अब मेट्रो के यात्रियों को सिक्के के आकार के टोकन से मुक्ति मिलेगी। नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर के स्टेशनों का प्रवेश द्वार क्यूआर (क्वीक रिस्पांस) कोड से खुलेगा। यही नहीं स्टेशनों से बाहर जाने में भी यही प्रक्रिया दोहरानी होगी। यह क्यूआर कोड या तो काउंटर पर पर्ची वाली टिकट या मोबाइल से बुक किए गए टिकट पर अंकित होगा।

एनएमआरसी के अधिकारियों की मानें तो नोएडा-ग्रेनो कॉरिडोर पर मोबाइल ऐप से टिकटों की बुकिंग होगी। इसके बाद ऐप से ही क्यूआर कोड भेजा जाएगा, जिसे स्टेशन में प्रवेश के दौरान ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट पर लगे यंत्र के सामने रखना होगा। इसके बाद गेट खुलेगा। यही प्रक्रिया बाहर निकलने के लिए होगी। ऐप एनएमआरसी का होगा, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा होगा। यात्री चाहे तो स्टेशनों पर बने काउंटरों से भी टिकट खरीद सकते हैं। ऐसी टिकट पर्ची वाली होगी, जिस पर क्यूआर कोड अंकित होगा। यहां पहले से चल रहा टोकन नहीं मिलेगा।

यह होता है क्यूआर कोड

क्वीक रिस्पांस कोड, मैट्रिक्स बार-कोड या दो आयामी बार-कोड का एक प्रकार का ट्रेडमार्क है जो सर्वप्रथम जापान में मोटर वाहन उद्योग के लिए बनाया गया था। कोड मशीन के सामने लाने पर पूरा ब्योरा मशीन पर दिखता है। यह फिल्मों के बुक किए गए टिकट में भी प्रयोग किया जाता है। यही प्रक्रिया मेट्रो में अपनाई जाएगी।

मोबाइल ऐप से होगी टिकटों की बुकिंग, पर्ची वाली टिकट भी मिलेंगी

नोएडा-ग्रेनो मेट्रो में क्यूआर कोड के माध्यम से गेट खुलेंगे। यह टिकट पर अंकित होगा। यह टिकट मोबाइल ऐप से बुक किए जा सकेंगे। इसके अलावा काउंटर से पर्ची वाले टिकटों पर भी यह अंकित होगा।

– पीडी उपाध्याय, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एनएमआरसी

स्टेशनों को अपना नाम दे सकेंगी कंपनियां

अमर उजाला ब्यूरो

नोएडा।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर पर बन चुके स्टेशनों के नाम का चयन कंपनियां कर सकेंगी। इसके लिए उनको टेंडर में शामिल होना होगा। जिसकी ज्यादा बोली होगी उसे उक्त स्टेशन का नाम अपनी कंपनी के नाम पर रखने का मौका मिलेगा। जिस तरह से नोएडा सिटी सेंटर का नाम वेव सिटी सेंटर रखा गया है। उसी तरह से इस कॉरिडोर पर किसी भी स्टेशन का नाम अपनी कंपनी, संस्था, एजेंसी, स्कूल, कॉलेज आदि के नाम पर रखा जा सकेगा। इसके लिए एनएमआरसी को-ब्रांडिंग पॉलिसी लेकर आ रही है। तैयार किए जा रहे बिजनेस मॉडल के तहत जल्द टेंडर जारी होगा।

नये कार्यालय का काम शुरू

सेक्टर-39 में 650 वर्गमीटर में एनएमआरसी कार्यालय का पहले से ही काम रहा है। यहीं एक और कार्यालय के लिए एनएमआरसी को 1600 वर्गमीटर का स्पेस मिला है। इस पर नए कार्यालय का निर्माण शुरू किया गया है। यहां दो निदेशकों, छह एचओडी के लिए कमरों के अलावा, कांफ्रेंस हॉल, मिनी ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, सिटी बस सेल और 50 कर्मचारियों के बैठने के लिए कमरे बनेंगे। पिछले सप्ताह शुरू किया गया काम तीन माह में पूरा होगा। इसकी लागत तीन करोड़ आएगी।

सीबीटीसी पद्धति पर चलेगी मेट्रो

नोएडा ग्रेनो मेट्रो कम्युनिकेशंस बेस्ड ट्रेन कंट्रोल (सीबीटीसी) सिस्टम पर चलेगी। यह मजेंटा लाइन में भी प्रयोग में लाया जाएगा। इसी सिस्टम के अध्ययन के लिए एनएमआरसी के एमडी आलोक टंडन इटली और डेनमार्क के दौरे पर गए थे। वहां मेट्रो सिस्टम के अलावा ट्रैक और सिग्नलिंग सिस्टम का उपयोग भी वहां के तर्ज पर किया जाएगा। दौरे में एएफसी गेट के फैक्ट्री का भी निरीक्षण किया गया।

सिटी बस को नहीं मिल रहा फंड

एनएमआरसी की सिटी बस सेवा को फंड देने से प्राधिकरण ने इंकार कर दिया है। एनएमआरसी के अधिकारियों के मुताबिक अपने स्रोत से इसे चलाने के लिए प्राधिकरण ने कहा है। यहां मार्च के बाद फंड नहीं दिया। इस वजह से सेवा आगे जारी रखने पर संकट पैदा हो गया है। इस बाबत प्राधिकरण के सीईओ से बातचीत चल रही है। एनएमआरसी की सिटी बस हर माह 1 करोड़ कमाती है। वहीं, तीन करोड़ के नुकसान में है। यही वजह है कि प्राधिकरण ने आगे फंड देने से मना कर दिया है।

दिसंबर तक सेक्टर-62 की शुरू करने का

अमर उजाला ब्यूरो

नोएडा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की ओर से सेक्टर-62 तक के मेट्रो परियोजना विस्तार को हरी झंडी मिलने से यहां के काम में तेजी आने की उम्मीद है। उम्मीद है जल्द ही मेट्रो का ट्रायल शुरू होगा। इस लाइन के शुरू होने के लिए दिसंबर 2018 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नोएडा सिटी सेंटर से सेक्टर-62 तक मेट्रो का काम काफी पहले से ही चल रहा है और यहां के पांच स्टेशन बन चुके हैं। वहीं छठे स्टेशन का काम जल्द पूरा होगा। यहां नोएडा सिटी सेंटर से चलने पर सेक्टर-34,52,61,59 व सेक्टर-62 और इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्टेशन तक यात्री जा सकेंगे। इस

ट्रै करीब इलेक स्ट

कॉरिडोर स्टेशन को कॉरिडोर है। इलेक शुरू होने 52, 34, 65, 66 रिहाइशी को एक के औद्यो संख्या मे करने अ सुविधा मि

बिजली चोरी के मामले में पक्ष र

नोएडा। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डीएमआरसी पर बिजली चोरी का आरोप लगाने प सिंह ने संज्ञान लिया है। सूत्रों की मानें तो उनकी पीवीवीएनएल के अधिकारियों के साथ एक बैठक हो का कहना है कि कुछ तकनीकी वजहों से यह समाधान करा लिया जाएगा। इस मामले में डीएम ओर से एनएमआरसी के एमडी और नोएडा-ग्रेटर आलोक टंडन को पत्र लिखकर समय मांगा है। दर से यह आरोप लगाया गया है कि बॉटेनिकल गार्डन चोरी की बिजली जलाई जा रही है। इसमें मेट्रो की का कनेक्शन दिया गया है। यही नहीं डीएमआरसी करवाया जा रहा है। विद्युत विभाग की ओर से एफआ